(b) The work which is proposed to be entrusted to the special cell is already being done in the appropriate Division of the Planning Commission. The proposal for the creation of additional posts for the purpose is awaiting sanction. As soon as the sanction is accorded and appointments are made to the newly-created posts, the work will be taken over by the special cell.

(c) It is proposed to hold an informal meeting of the Planning Commission to which Members of Parliament from the Hill areas will be invited for a preliminary exchange of views. At this meeting the appropriate procedure and method of consultation between the Planning Commission and the Members of Parliament for continuous liaison and review of the problems of the hill areas and the progress made towards their solution, will be considered.

ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वासित किये गये स्वतंत्रता सेनानियों अथवा जिन्होंने फर्जी नाम लिखवाये, को पेंशन देना

574. **श्री लम्बोदर बलियार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वासित कर दिया गया था अथवा गिरफ्तार होने पर जिन्होंने फर्जी नाम लिखाये जिससे जुर्माना अदा न करना पड़े, स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में पेंशन पाने के लिये शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा और यह पेंशन सही व्यक्तियों को ही दी जाये, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के कितने लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्कासित किये गये व्यक्तियों को आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर पेंशन देने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा बशर्ते कि निष्कासन की अवधि छः महीने अथवा अधिक की हो । जिन व्यक्तियों ने गिरफ्तार होने पर झूठे नाम दिये थे ताकि उन्हें जुर्माना न देना पड़े, उन व्यक्तियों पर भी संसद सदस्यों / भूतपूर्व संसद सदस्यों / विधायकों / भूतपूर्व विधायकों के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में रहे थे, पेंशन स्वीकृति के लिये विचार किया जायेगा ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 29 जुलाई, 1972 तक उन जिलों से जिनमें आदिवासी क्षेत्र हैं, 1,146 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । मामलों की संवीक्षा की जा रही है और जब तक सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आदिवासी क्षेत्र के उन व्यक्तियों की संख्या बतलाना सम्भव नहीं है जिन्हें केन्द्रीय पेंशन के अधीन पेंशन से लाभ होने की सम्भावना है ।

Objectives outlined in the approach paper on the Fifth Five Year Plan

575. SHRI NARENDRA SINGH : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the policy implications of the objectives, like the production and distribution of essential items of consumption, outlined in the approach paper on the 5th Five Year Plan, have been worked out ;

(b) if so, the broad features thereof ; and

(c) if not the date by which these are likely to be worked out for inclusion in the 5th Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Some clear picture about the Fifth Plan is likely to emerge only by the end of 1973.

Sheikh Abdullah's statement regarding treating of Kashmiris as in the Case of of East Bengalis

576. SHRI NARENDRA SINGH : Will